गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 140
दि. 19.09.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

प्रधानमंत्री ने नेपाल की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और भारत सरकार तथा भारत के लोगों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दीं। श्री मोदी ने नेपाल में हाल में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान-माल के नुकसान पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच विशेष सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के लिए घनिष्ठतापूर्वक कार्य जारी रखने के प्रति भारत की तत्परता व्यक्त की।

'मैं भारत और पीएम मोदी के बहुत करीब...', रूस से तेल खरीद पर आलोचना के बाद बदले ट्रंप के सुर

ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर अपने रिश्ते का जिक्र किया.

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी करीबी दोस्ती का जिक्र किया. रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद ट्रंप ने भारत के प्रति नरम रुख अपनाया है. हालांकि ट्रंप ने यूरोपीय देशों और चीन की आलोचना की और कहा कि वैश्विक तेल की कीमतें घटाकर रूस को समझौते के लिए मजबूर किया जा सकता है.

रूस से तेल खरीदने पर कई महीनों तक टैरिफ की धमकी देने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख भारत के प्रति नरम होता दिख रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर जोर देना शुरू कर दिया है. पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के 2 दिन बाद ही ट्रंप ने ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ पत्रकारों से बात करते हुए एक बार फिर अपने रिश्ते का जिक्र किया.

ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के बहुत करीब हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीब हूं, मैंने उनसे पिछले दिनों बात की थी. मैंने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं.

ट्रंप की ये टिप्पणी उस समय आई है, जब उन्होंने यूरोपीय देशों की आलोचना की कि वे अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. उनका कहना है कि ऐसा करने से मौजूदा संघर्षों में रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कमजोर पड़ती है. भारत द्वारा रूसी तेल खरीद पर लगातार नाराजगी जताने के बावजूद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने करीबी रिश्तों पर जोर दिया. साथ ही कहा कि वैश्विक तेल कीमतें घटाना रूस को समझौते के लिए मजबूर करने का सबसे बड़ा उपाय है.

'यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे'

ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि यूरोपीय देश अब भी रूस से तेल खरीद रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने तो उन पर पहले ही प्रतिबंध लगाए हैं.

केंद्रीय मंत्री श्री सबार्नंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उत्सव का नेतृत्व किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (एमओपीएसडब्ल्यू) मंत्री, श्री सबार्नंद सोनोवाल ने बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में डिब्रूगढ़ में एक भव्य समारोह का नेतृत्व किया, जो देश भर में शुरू किए गए 'स्वस्थ नारी-सबल परिवार अभियान' और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह की तर्ज पर था।

मध्य प्रदेश से, प्रधानमंत्री मोदी ने इन पहलों को राष्ट्र को समर्पित किया, और शानदार स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर पोषण और मजबूत परिवार सुनिश्चित करने के अपने विजन को रेखांकित किया। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने एक दिवसीय कार्यक्रम का नेतृत्व किया और प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी एजेंडे के प्रति असम की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस कार्यक्रम में नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, महिला समूहों और सामुदायिक नेताओं को एक साथ

लाया गया।

इन स्थानीय समारोहों में जन-केंद्रित पहलों की एक श्रृंखला शामिल थीः निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच, अनिवार्य दवाओं का वितरण और एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। ये गतिविधियाँ निवारक स्वास्थ्य-रक्षा, पोषण और सामुदायिक सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार की गई थीं। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए इन्हें जरूरी बताते हुए, बार-बार जोर दिया है।

श्री सबार्नंद सोनोवाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, "आज न केवल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का जन्मदिन है, बल्कि यह वह दिन भी है जब भारत उत्तम स्वास्थ्य, सुदृढ़ परिवारों और महिला-नेतृत्व वाले विकास के मिशन के लिए स्वयं को पुनः समर्पित कर रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "असम के एक बेटे के रूप में, मुझे यह देखकर गर्व होता है कि डिब्रूगढ़ इस राष्ट्रीय आंदोलन में पूरे मनोयोग से योगदान दे रहा है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की ओर से मैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत नई दिल्ली में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व करते हुए सेवा पखवाड़ा में भागीदारी की।

श्री यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में, सभी भारतीयों से धरती माता के नाम पर एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया था। श्री भूपेन्द्र यादव ने आगे कहा कि 'एक पेड़ माँ के नाम 2.0' अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, बल्कि इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

सेंट्रल रिज, पीबीजी पोलो ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के लगभग 70 राजनयिक और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे।

भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठित ग्रुप 'ए' कैडर, भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा (आईडीएसई) ने 17 सितंबर, 2025 को दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया। रक्षा सचिव श्री

राजेश कुमार सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने में आईडीएसई कैडर के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने एनई-स्पार्क्स कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो का दौरा करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के साथ बातचीत की

(जीएनएस)।

केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने पूर्वोत्तर राज्यों के स्कूली छात्रों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। ये छात्र एनईएसएसी-इसरो और 8 पूर्वोत्तर राज्य सरकारों के सहयोग से एमडोनर के एनई-स्पार्क्स कार्यक्रम के अंतर्गत इसरो मुख्यालय आए थे। बातचीत के दौरान, छात्रों ने इसरो सुविधाओं का दौरा करने और अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति के बारे में जानने के अपने अनुभव साझा किए। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने उनके उत्साह की सराहना की और उन्हें वैज्ञानिक जिज्ञासा को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

'अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुँच और ज्ञान के लिए पूर्वोत्तर छात्रों का कार्यक्रम' (एनई-स्पार्क्स), 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित एक प्रमुख पहल है, जो पूर्वोत्तर के छात्रों को इसरो की अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीक से परिचित कराती है, जिसका लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) के क्षेत्रों में उनकी रुचि जगाना है।

इस कार्यक्रम में 800 मेधावी विज्ञान छात्रों (पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य से 100) के लिए बेंगलुरु स्थित प्रमुख इसरो केन्द्रों का भ्रमण शामिल है।

एनई-स्पार्क्स कार्यक्रम के तहत छात्रों के चार बैचों ने सफलतापूर्वक अपना दौरा पूरा कर लिया है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 394 छात्रों (189 छात्र और 205 छात्राएँ) को एक गहन शिक्षण अनुभव प्राप्त हुआ। प्रत्येक बैच में पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के छात्र शामिल थे, जिनके साथ उनके राज्य समन्वयक, एनईसी और एनईएसएसी के समन्वयक भी थे। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने प्रमुख इसरो केन्द्रों का दौरा करने वाले लगभग 100 छात्रों से आज मुलाकात की और कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे फीडबैक लिया।

बातचीत के दौरान, केन्द्रीय मंत्री ने छात्रों के उत्साह और जिज्ञासा की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि 'अंतरिक्ष अंतिम सीमा है और भारत आप बच्चों की प्रेरणा के कारण ही आगे बढ़ रहा है।' उन्होंने चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 तथा आगामी गगनयान मिशन सहित भारत की हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और हर क्षेत्र के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के छात्रों ने अपने अनुभवों पर अत्यन्त गहरे विचार साझा किए, जिनमें उपग्रह एकीकरण देखने से लेकर इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिकों से बातचीत तक शामिल थी।

कई छात्रों ने अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं में नई स्पष्टता और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में करियर बनाने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। केन्द्रीय मंत्री के प्रोत्साहन भरे शब्दों ने, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों के छात्रों के लिए, कार्यक्रम के समावेशी नजरिये पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "हर बच्चे में एक चिंगारी होती है, जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता की एक चिंगारी, जो देश और दुनिया के किसी भी हिस्से से चमक सकती है।" कार्यक्रम विचारों के जीवंत आदान-प्रदान के साथ संपन्न हुआ, जिसने पूर्वोत्तर के भावी वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों को आगे बढ़ाने में एनई-स्पार्क्स की भूमिका की पुष्टि की।

800 छात्रों के समग्र लक्ष्य की दिशा में व्यापक पहुंच और अधिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ निकट समन्वय में आगामी बैचों की योजना बनाई गई है।

कृषि मशीनरी पर जीएसटी सुधारों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे बैठक

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल 19 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रीकरण संघ (TMA), कृषि मशीनरी निमार्ता संघ (AMMA), अखिल भारतीय कम्बाइन हार्वेस्टर निमार्ता संघ (AICMA) तथा पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PTAI) सहित अन्य संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह की पहल पर आयोजित इस बैठक का उद्देश्य कृषि मशीनरी एवं उपकरणों पर हाल ही में घोषित जीएसटी दरों में कमी (12-18% से घटाकर 5%) के निर्णय पर चर्चा करना।

केरल की राज्य मंत्री श्रीमती वीना जॉर्ज ने केरल में 'आयुष सेक्टर में आईटी समाधान' पर आयोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

केरल सरकार की स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती वीना जॉर्ज ने आज केरल के कुमारकोम स्थित मनोरम केटीडीसी वाटरस्केप्स में 'आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। केरल के राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 प्रतिनिधियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निमार्ताओं सहित 155 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यह कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित आयुष विभागीय शिखर सम्मेलन 2025 की प्राथमिकताओं के अनुरूप आयोजित की गई थी।

श्रीमती वीना जॉर्ज ने अपने उद्घाटन भाषण में, प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया और कुमारकोम की प्राकृतिक संरचना के प्रतीकात्मक चयन पर जोर

दिया, जो आयुष द्वारा प्रचारित सद्भाव को दर्शाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रौद्योगिकी प्रगति को तेजी से अपनाने के साथ-साथ पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।

श्रीमती वीना जॉर्ज ने डिजिटल उपकरणों को स्वास्थ्य इको-सिस्टम में सहजता से एकीकृत करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया—जो वास्तविक समय की निगरानी, बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन, मजबूत डेटा ढांचे और अधिक सुलभ और किफायती देखभाल के लिए पारदर्शी वित्तीय ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से एक केंद्रीकृत, अंतःक्रियाशील डिजिटल ढांचे के लिए सहयोगात्मक रूप से रोडमैप तैयार करने का आ'ान किया जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मजबूत करे और कोई भी इसके लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 'मिशन फोर मिलियन ट्रीज' अभियान अंतर्गत राणिप वॉर्ड में वृक्षारोपण किया

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 18 सितंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद महानगर पालिका द्वारा 'मिशन फोर मिलियन ट्रीज' अभियान अंतर्गत गुरुवार को राणिप वॉर्ड में साबरमती जेल के पीछे गार्डन में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पदाधिकारियों के साथ सामूहिक वृक्षारोपण किया।

श्री पटेल ने अहमदाबाद मनपा द्वारा 'एक पेड़ माँ के नाम' तथा 'मिशन फोर मिलियन ट्रीज' अभियान में वृक्षारोपण कर हरित गुजरात का संदेश दिया और साथ ही नागरिकों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने, उनका संरक्षण करने तथा हरियाला गुजरात बनाने में सहभागी होने का आ'ान किया।

यहाँ उल्लेखनीय है कि शहर का ग्रीन कवर बढ़ान के उम्दा आशय के साथ अहमदाबाद मनपा द्वारा 'मिशन फोर मिलियन ट्रीज' अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। गत वर्ष फोर मिलियन ट्रीज अभियान के लिए किए गए सटीक सूक्ष्म आयोजन तथा तद्अनुसार वास्तविक क्रियान्वयन के कारण 7 सितंबर तक 40 लाख 80 हजार 180 पौधों की बुवाई पूर्ण हुई है।

इतना ही नहीं; पवित्र श्रावण माह के चार सोमवारों को अहमदाबाद मनपा के सभी जोनों में कुल तुलसी के 54,883 पौधों का वितरण किया गया। श्रावण के दौरान आई एकादशियों के दिन सभी जोनों में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कदम्ब, पीपल, समी, सेवन, सीता अशोक तथा बिल्व जैसे पेड़-पौधों सहित कुल 491 पेड़-पौधों का वितरण-बुवाई कार्य किया गया।

प्रधानमंत्री के जन्म दिवस यानी 17 सितंबर बुधवार को अहमदाबाद महानगर के हर वॉर्ड में एक धार्मिक स्थल पर तुलसी वितरण कार्यक्रम द्वारा 12,820 तुलसी पौधों का वितरण किया गया। इस मिशन फोर मिलियन ट्रीज अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए स्थलों को गूगल मैप से खोजा जाता है। इसके अलावा; हर बुवाई स्थल की जियो टैगिंग की जाती है तथा एलआईडीएआर सर्वे टेक्नोलॉजी द्वारा पेड़-पौधों की वृद्धि एवं सर्वाइवल रेट की मॉनिटरिंग भी महानगर पालिका द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से पुत्रजीवा पौधे की बुवाई के साथ राणिप वॉर्ड में साबरमती जेल के पीछे स्थित गार्डन में गुरुवार को आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 4300 वर्ग मीटर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से आयुर्वेदिक सहित लगभग 14 हजार पेड़-पौधों की बुवाई का आयोजन है।

सम्पादकीय

पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप के दावे की पोल खोली

पाकिस्तान से दो ऐसी स्वीवृति आईं हैं जो न सिर्प भारत के ऑपरेशन सिदूर में भारत की सफलता का ही उल्लेख करती है बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को भी खारिज करती हैं। इनसे इस बात की भी पुष्टि होती है जो भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी दावा करते आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैश-ए-मोहम्मद के नंबर दो कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी की। इलियास कश्मीरी ने स्वीकार किया है कि आतंकी संगठन के बहावलपुर मुख्यालय पर भारतीय सेना के हमले में उसके संस्थापक मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के चीथड़े उड़ गए थे। मैं अपने परिवार के सदस्यों के मारे जाने की बात स्वीकार करता हूं। मंगलवार को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में जैश-ए-मोहम्मद कमांडर इलियास कश्मीरी को भारतीय हमले के खिलाफ जहर उगलते सुना जा सकता है। जिसमें अजहर के परिवार के सदस्य मारे गए थे। यह वीडियो 6 सितम्बर को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए मिशन मुस्तफा सम्मेलन का बताया जा रहा है। कई बंदूकधारियों के बीच खड़े जैश कमांडर ने कहा इस देश की वैचारिक और भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए हमने दिल्ली, काबूल और वंधार पर हमला किया (जेहाद छेड़ा) और अपना सब वुछ वुर्बान करने के बाद सात मई को बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों को भारतीय हमलों में टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिदूर के तहत पाकिस्तान व गुलाम कश्मीर में लश्कर व जैश के मुख्यालय समेत 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। अजहर ने खुद कहा था कि बहावलपुर में भारतीय हमले में मरने वालों में उसकी बड़ी बहन और उसके पति, एक भतीजा व उसकी पत्नी, एक अन्य भतीजी व परिवार के पांच बच्चे शामिल थे यानि वुल मिलाकर दस ज्यादा मारे गए थे। इसी से साबित होता है कि भारतीय सेना का निशाना कितना सटीक था। अब बात करते हैं ताऊ ट्रंप के दावों की। पाकिस्तान के उप-प्राधानमंत्री और विदेश मंत्री इशार डार ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम कराने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की ही पोल खोल दी है। डार ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान उनसे कहा था कि भारत ने युद्ध विराम के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इंकार कर दिया था क्योंकि यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है। जब डार से भारत के साथ वार्ता या तीसरे पक्ष की भागीदारी को लेकर पाकिस्तान के रुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह एक द्विपक्षीय मामला है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि उन्होंने दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच युद्ध विराम करवाया। ट्रंप 10 मई के संघर्ष विराम के बाद से 30 से ज्यादा बार दोनों देशों में संघर्ष विराम का दावा कर चुके हैं। इशाक डार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत ने अमेरिका सहित किसी भी देश की मध्यस्थता से साफ इंकार कर दिया है। डार ने ट्रंप की पोल खोल दी है।

टेक्नोलॉजी के चैंपियन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी: अश्विनी वैष्णव

क्या आपको वह समय याद है जब सरकारी दस्तावेज को हासिल करना कितना मशक्कत का काम होता था ? कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लंबी लाइनें लगती थीं, और कभी-कभी बेवजह की फीस देनी पड़ती थी। अब वही दस्तावेज सीधे आपके फोन पर मिल जाते हैं।

यह बदलाव यूं ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को भारत का सबसे बड़ा समान अवसर देने वाला साधन बना दिया। मुंबई का एक रेहड़ी-पटरी वाला वाला भी वही यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल करता है, जो एक बड़ी कंपनी का अधिकारी करता है। उनकी सोच में तकनीक पद के अनुरूप किसी ऊंच-नीच को नहीं मानती।

यह बदलाव उनकी मूल सोच अंत्योदय को दशार्ता है- यानी कतार में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। हर डिजिटल पहल का मकसद है कि तकनीक को सबके लिए समान रूप से उपलब्ध कराना। गुजरात में शुरू हुए ये प्रयोग ही भारत की डिजिटल क्रांति की नींव बने।

गुजरातः जहां से शुरूआत हुई

मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने तकनीक और नवाचार के जरिए गुजरात को बदला। 2003 में शुरू की गई ज्योतिग्राम योजना में फीडर सेपरेशन तकनीक का उपयोग किया गया। इससे ग्रामीण उद्योगों को 24७7 बिजली मिली और तय समय पर खेतों को बिजली मिलने से जमीन के नीचे का पानी कम गति से घटने लगा।

महिलाएं रात में पढ़ाई कर सकीं और छोटे व्यवसाय फले-फूले, जिससे गाँव से शहर की ओर पलायन घटा। एक अध्ययन के अनुसार, इस योजना पर किए गए 1,115 करोड़ रुपये के निवेश की भरपाई सिर्फ. ढाई साल में हो गई।

2012 में उन्होंने नर्मदा नहर पर सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया। इस परियोजना से हर साल 1.6 करोड़ यूनिट बिजली बनी, जो लगभग 16,000 घरों के लिए काफी थी। साथ ही, नहर के पानी का वाष्पीकरण कम हुआ और पानी की उपलब्धता बढ़ी।

एक ही पहल से कई समस्याओं का समाधान निकालना मोदी जी की तकनीक दृष्टि को दशार्ता है। स्वच्छ ऊर्जा बनाना और पानी बचाना, दोनों साथ-साथ। यह दक्षता और प्रभाव का उदाहरण था, जो साधारण समाधानों से कहीं अधिक था।

इस नवाचार को अमेरिका और स्पेन द्वारा अपनाया जाना इसकी प्रभावशीलता को और मजबूत करता है।

ई-धरा प्रणाली से जमीन के कागजात डिजिटल हुए। स्वागत पहल से नागरिक वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ सके। ऑनलाइन टेंडरिंग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी।

इन पहलों से भ्रष्टाचार घटा और सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई। लोगों का शासन पर भरोसा लौटा, जिसका असर गुजरात में लगातार मिलती बड़ी चुनावी सफलताओं में दिखा।

राष्ट्रीय परिदृश्य

2014 में उन्होंने गुजरात का अनुभव और सीख को दिल्ली तक पहुंचाया। लेकिन पैमाना कहीं बड़ा था।

उनके नेतृत्व में इंडिया स्टैक ने जो आकार लिया, वह दुनिया का सबसे समावेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर उभरा है। इसकी बुनियाद जैम ट्रिनिटी (जन धन, आधार, मोबाइल) पर रखी गई।

जन धन खातों ने 53 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। जो लोग अब तक आर्थिक रूप से बाहर थे, वे पहली बार औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने।

ठेले वाले, दिहाड़ी मजदूर और ग्रामीण परिवार, जो केवल नकद पर निर्भर रहते थे, अब बैंक खातों से जुड़े। इससे उन्हें सुरक्षित बचत करने, सीधे सरकारी लाभ पाने और आसानी से कर्ज.प्राप्त करने का अवसर मिला।

आधार ने नागरिकों को डिजिटल पहचान दी। अब तक 142 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। इससे सरकारी सेवाओं तक पहुंचना आसान हुई, जहां पहले कई दस्तावेजों की जांच की जरूरत पड़ती थी।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) ने बिचौलियों को हटा दिया और गड़बड़ी कम की। अब तक डीबीटी से 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। यही पैसा स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे बनाने में लगाया जा रहा है।

पहले ग्राहक की पहचान (केवाईसी) की प्रक्रिया कठिन थी। इसमें कागजी दस्तावेजों की जांच, मैनुअल प्रक्रिया और कई बार की भाग-दौड़ शामिल होती थी। इससे सेवा प्रदाताओं को हर वेरिफि केशन पर काफी खर्च करना पड़ता था। आधार-आधारित ई-केवाईसी ने इस खर्च को घटाकर मात्र 5 रुपये में कर दिया। अब छोटे से छोटे लेन-देन भी आर्थिक रूप से संभव हो गए हैं।

यूपीआई ने भारत के भुगतान करने का तरीका बदल दिया। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। सिर्फ. अगस्त 2025 में ही 20 अरब से अधिक लेन-देन हुए, जिनकी कुल राशि 24.85 लाख करोड़ रुपये रही।

अब पैसे भेजना बैंक में घंटों की परेशानी नहीं, बल्कि मोबाइल पर 2 सेकंड से भी कम का काम है। बैंक जाने, लाइन लगाने और कागजी प्रक्रिया की जगह अब क्यूआर कोड स्कैन से तुरंत भुगतान हो जाता है।

आज भारत दुनिया के कुल रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स का आधा हिस्सा अकेले संभालता है। दस साल पहले भारत ज्यादातर नकद पर निर्भर था। प्रधानमंत्री मोदी की सोच ने जैम ट्रिनिटी और यूपीआई ढांचे को अंतिम रूप दिया।

जब कोविड आया और उन्होंने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया, तो यह पूरा सिस्टम कामयाब साबित हुआ। नतीजा यह है कि आज यूपीआई, वैश्विक स्तर पर वीजा से भी अधिक लेन-देन करता है। एक साधारण मोबाइल फोन अब बैंक, पेमेंट गेटवे और सर्विस सेंटर... सब कुछ बन गया है।

प्रगति ने शासन में जवाबदेही लाने का काम किया। यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री को सीधे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग से जोड़ता है, जहां हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होती है। जब अधिकारियों को पता होता है कि प्रधानमंत्री लाइव वीडियो में उनका काम देखेंगे, तो जवाबदेही अपने आप बढ़ जाती है।

जैसे किसी राजमार्ग परियोजना में देरी हो रही हो, तो प्रगति समीक्षा के दौरान तुरंत उस पर ध्यान दिया जाता है और अधिकारियों को देरी का कारण बताना पड़ता है। इससे तुरंत सुधार होता है और आखिरकार जनता को सीधा लाभ मिलता है।

सबके लिए तकनीक

तकनीक ने खेती और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बदल दिया है। हरियाणा के किसान जगदेव सिंह अब फसल से जुड़े फैसले लेने के लिए एआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मौसम की जानकारी और मिट्टी की सेहत का डेटा सीधे मोबाइल पर मिल जाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए 11 करोड़ किसानों को सीधी आय सहायता डिजिटल माध्यम से पहुंचाई जाती है।

डिजी-लॉकर के अब 57 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं, जिनमें 967 करोड़ दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे गए हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, डिग्री सर्टिफि केट, आधार और अन्य सरकारी दस्तावेज अब आपके फोन में सुरक्षित रहते हैं।

सड़क पर पुलिस चेकिंग के दौरान अब कागज ढूंढने की जरूरत नहीं। बस डिजी-लॉकर से डिजिटल लाइसेंस दिखा दीजिए। आधार ऑथेंटिकेशन से आयकर रिटर्न भरना भी बेहद आसान हो गया है। जहां पहले ढेर सारे दस्तावेजों की फाइलें साथ ले जानी पड़ती थीं, अब सब कुछ आपकी जेब में मोबाइल पर समा गया है।

अंतरिक्ष और नवाचार

भारत ने वह कर दिखाया जो असंभव सा लगता था। मंगल तक पहली कोशिश में पहुंचना और वह भी इतने कम खर्चे में, जितना एक हॉलीवुड फि ल्म पर भी नहीं लगता। मंगलयान मिशन केवल 450 करोड़ में पूरा हुआ, जिसने साबित किया कि भारतीय इंजीनियरिंग विश्वस्तरीय नतीजे दे सकती है।

चंद्रयान-3 ने भारत को चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया और चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश।

इसरो ने एक ही मिशन में 104 उपग्रह छोड़े, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। अब भारतीय रॉकेट 34 देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में पहुँचा रहे हैं। गगनयान मिशन भारत को चौथा ऐसा देश बनाएगा जो अपनी स्वदेशी तकनीक से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। प्रधानमंत्री मोदी हमारे वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं।

वैश्विक नेतृत्व

जब कोविड-19 आया, तो पूरी दुनिया वैक्सीन बांटने की अफरा-तफरी से जूझ रही थी। भारत ने अपनी ताकत दिखाते हुए समाधान दिया। कोविन प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड समय में बनाया गया। यह दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का एक संपूर्ण डिजिटल समाधान था।

इस प्लेटफॉर्म ने 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज को सटीक डिजिटल ढंग से संभाला। न कोई ब्लैक मार्केटिंग, न पक्षपात सिर्फ. पारदर्शी वितरण।

डायनैमिक एलोकेशन की वजह से बबार्दी रुकी। बची हुई वैक्सीन तुरंत उन इलाकों में भेज दी जाती थी जहां ज्यादा जरूरत थी। यह उपलब्धि दिखाती है कि जब तकनीक को राजनीतिक इच्छाशक्ति का सहारा मिलता है, तो वह बहुत बड़े स्तर पर और पूरी निष्पक्षता के साथ परिणाम दे सकती है।

मैन्युफैक्चरिंग क्रांति

चीजें बनाने का असली नियम यह है कि आप सीधे चिप्स बनाने पर नहीं कूद सकते, पहले बुनियादी चीजें सीखनी पड़ती हैं। यह बिल्कुल वैसे है जैसे कोडिंग सीखते समय सबसे पहले 'हैलो वर्ल्ड' से शुरूआत होती है, उसके बाद ही बड़े ऐप्स बनाए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन भी इसी क्रम का पालन करता है। देश पहले असेंबली में महारत हासिल करते हैं, फिर सब-मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स और उपकरणों तक आगे बढ़ते हैं। भारत की यात्रा भी इसी प्रगति को दशार्ती है।

प्रधानमंत्री की दृष्टि के तहत, आज हमारी मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमता हमें उन्नत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की ओर छलांग लगाने में मदद कर रही है।

भारत लंबे समय से डिजाइन टैलेंट का केंद्र रहा है। दुनिया के 20% से ज्यादा चिप डिजाइनर यहीं हैं। अब भारत 2 नैनोमीटर (एनएम), 3 एनएम और 7 एनएम जैसे एडवांस्ड चिप्स डिजाइन करने में सक्षम है। ये चिप्स भारत में डिजाइन होकर दुनिया भर के लिए बनाए जा रहे हैं।

वर्तमान में फैब्स और पैकेजिंग फैसिलिटीज बनाने पर फोकस करना इस प्राकृतिक विकास का अगला कदम है। लेकिन यह सोच केवल निर्माण तक सीमित नहीं है। सेमीकंडक्टर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स, गैस और विशेष सामग्री को भी समर्थन दिया जा रहा है।

इससे केवल फैक्ट्रियाँ नहीं, बल्कि एक पूरा ईकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की वैल्यू चेन की गहरी समझ से संभव हुई है। क्षमता को कदम-दर-कदम विकसित करना और हर चरण को मजबूत बनाना, उसके बाद ही अगले स्तर पर बढ़ना।

बुद्धिमत्ता से युक्त बुनियादी ढाँचा

पीएम गति शक्ति पोर्टल जीआईएस तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। हर बुनियादी ढांचे की परियोजना डिजिटल रूप से मैप की जाती है। सड़कें, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह अब साथ में योजना बनाकर तैयार होते हैं। अब अलग-अलग विभागों में बिखरा काम नहीं, और न ही तालमेल की कमी से होने वाली देरी।

इंडिया एआई मिशन के तहत 38,000 से अधिक जीपीयू उपलब्ध कराए गए हैं, वह भी वैश्विक लागत के एक-तिहाई दाम पर। इससे स्टार्टअप, शोधकताओं और छात्रों को सिर्फ. 67 रुपये प्रति घंटे की दर पर सिलिकॉन वैली जैसी कंप्यूटिंग सुविधा मिली है।

एआईकोश प्लेटफॉर्म पर 2,000 से ज्यादा डेटा सेट मौजूद हैं। मौसम से लेकर मिट्टी की सेहत तक। इन्हीं की मदद से भारत की भाषाओं, कानूनों, स्वास्थ्य प्रणालियों और वित्त क्षेत्र के लिए स्थानीय एलएलएम विकसित किए जा सकते हैं।

तकनीक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की समझ भारत की अनूठी एआई रेगुलेशन नीति में भी दिखाई देती है। दुनिया के केवल बाजार-आधारित या सरकार-नियंत्रित मॉडल से अलग, वे एक विशिष्ट टेक्नो-लीगल फ्रेमवर्क की कल्पना करते हैं।

सख़्त नियम बनाकर नवाचार को रोकने के बजाय, सरकार तकनीकी सुरक्षा उपायों में निवेश करती है। विश्वविद्यालय और आईआईटी मिलकर डीपफेक, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एआई-आधारित उपकरण विकसित कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण नवाचार को बढ़ावा देता है और साथ ही सुनिश्चित करता है कि तकनीक ज़िम्मेदारी के साथ लागू हो।

बुनियादी ढाँचे में तकनीक

केवड़िया में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 3डी मॉडलिंग और ब्रॉन्ज क्लैडिंग तकनीक से बनी यह प्रतिमा हर साल लगभग 58 लाख पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस परियोजना से हजारों नौकरियाँ बनीं और केवड़िया एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन गया।

चिनाब पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो कश्मीर को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। आइजोल रेल लाइन कठिन पहाड़ी इलाके से होकर गुजरती है और इसमें हिमालयन टनलिंग मेथड का प्रयोग किया गया है, जिसमें कई सुरंगें और पुल शामिल हैं। नया पंबन पुल सौ साल पुराने ढांचे की जगह आधुनिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है।

ये सिर्फ. इंजीनियरिंग की अद्भुत कृतियां नहीं हैं, बल्कि यह मोदी जी की उस सोच को दशार्ते हैं जिसमें तकनीक और दृढ़ संकल्प के सहारे भारत को जोड़ा जा रहा है।

मानव जुड़ाव

प्रधानमंत्री मोदी तकनीक को समझते हैं, लेकिन इंसानों को उससे भी बेहतर समझते हैं। उनकी अंत्योदय की सोच ही हर डिजिटल पहल को आगे बढ़ाती है। यूपीआई कई भाषाओं में काम करता है। सबसे गरीब किसान और सबसे अमीर उद्योगपति, दोनों की एक जैसी डिजिटल पहचान है।

सिंगापुर से लेकर फ्रांस तक कई देश यूपीआई से जुड़े हैं। जी-20 ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समावेशी विकास के लिए अहम् माना है। जापान ने इसके लिए पेटेंट भी दिया है। जो शुरूआत में भारत का समाधान था, वही अब पूरी दुनिया के लिए डिजिटल लोकतंत्र का मॉडल बन गया।

गुजरात में शुरूआती प्रयोगों से लेकर डिजिटल इंडिया के शुभारंभ तक की यात्रा यह दिखाती है कि तकनीक में बदलाव लाने की शक्ति है। मोदी जी ने तकनीक को शासन की भाषा बना दिया है। उन्होंने साबित किया है कि जब नेता तकनीक को इंसानियत के साथ अपनाते हैं, तो पूरा देश भविष्य की ओर बड़ी छलांग लगा सकता है।

(लेखक भारत सरकार के रेल,

सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए कम जीएसटी का लाभ सुनिश्चित करते हुए उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम किया

विधिक माप-विज्ञान नियमों में ढीलः संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के लिए समाचार पत्र में सूचना की आवश्यकता नहीं

संशोधित कीमतों के साथ पुरानी पैकेजिंग का उपयोग मार्च 2026 तक किया जा सकता है

(जीएनएस)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने 22 सितंबर 2025 से प्रभावी जीएसटी दरों में संशोधन के मद्देनजर एक संशोधित परामर्श जारी किया है। विधिक माप-विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम 2011 के नियम 33 के अंतर्गत , केंद्र सरकार ने उद्योग पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए ढील दी है और यह सुनिश्चित किया है कि कम जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचे।

परामर्श के अनुसार निमार्ता, पैकर्स और आयातक 22 सितंबर 2025 से पहले निर्मित बिना बिके पैकेजों पर स्वेच्छा से संशोधित मूल्य स्टिकर लगा सकते हैं, बशर्ते कि पैकेज पर छपी मूल एमआरपी अस्पष्ट न हो। यह स्पष्ट किया गया है कि नियम इस तरह के पुनः स्टिकर लगाने को अनिवार्य नहीं बनाते हैं और यह उन कंपनियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक है, जो संशोधित मूल्य घोषित करना चाहती हैं।

इसके अलावा नियम 18(3) के अंतर्गत दो समाचार पत्रों में संशोधित एमआरपी प्रकाशित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बजाय, निमार्ताओं और आयातकों को अब केवल थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को संशोधित मूल्य सूची देनी होगी। इसकी प्रतियाँ केंद्र सरकार में विधिक माप विज्ञान निदेशक और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विधिक माप विज्ञान नियंत्रकों को भेजी जाएँगी। इससे अनुपालन सरल होगा और उद्योग पर प्रक्रियात्मक बोझ कम होगा।

परामर्श में जीएसटी संशोधन से पहले से छपी पुरानी पैकेजिंग सामग्री या रैपरों को 31 मार्च 2026 तक या स्टॉक समाप्त होने तक जो भी पहले हो तक उपयोग की भी अनुमति दी गई है। कंपनियाँ ऐसी पैकेजिंग पर किसी भी उपयुक्त स्थान पर मुहर, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग करके अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित कर सकती हैं।

इसके अलावा सरकार ने निमार्ताओं, पैकर्स और आयातकों को सलाह दी है कि वे डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को संशोधित जीएसटी दरों के बारे में सूचित करने के लिए कदम उठाएँ। उन्हें उपभोक्ता जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया सहित सभी संभव संचार माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

यह कदम उद्योगों पर अनुपालन का अत्यधिक बोझ न पड़े और उपभोक्ताओं को जीएसटी में कमी का अपेक्षित लाभ मिले यह सुनिश्चित करते हुए व्यापार में आसानी और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है।

भारत और एफएओ में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए करार; क्षमता निर्माण श्रृंखला पर पहला वेबिनार आयोजित

(जीएनएस)।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ) ने भारत में ब्लू पोर्ट अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (टीसीपी) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अनुरूप, मत्स्य पालन विभाग ने क्षमता निर्माण और वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने के लिए तीन वेबिनार और भौतिक कार्यशालाओं की श्रृंखला के हिस्से के रूप में एफएओ के टीसीपी कार्यक्रम के तहत आज पहला वेबिनार आयोजित किया। डीओएफ के सचिव डॉ अभिलक्ष लिखी ने "ब्लू पोर्ट की नींवः मछली पकड़ने के बंदरगाहों में मूल्य सृजन" विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार में भारत में एफएओ प्रतिनिधि श्री ताकायुकी हागिवारा ने भी भाग लिया।

अपने संबोधन के दौरान, डॉ. अभिलक्ष लिखी ने इस बात पर जोर दिया कि मछली पकड़ने के बंदरगाह केवल भौतिक अवसंरचनाएं नहीं हैं, बल्कि आर्थिक समृद्धि, पारिस्थितिक स्थिरता और सामाजिक समावेश के कार्यनीतिक प्रवेश द्वार हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य पालन प्रणालियों के विकास के सरकार के विजन को

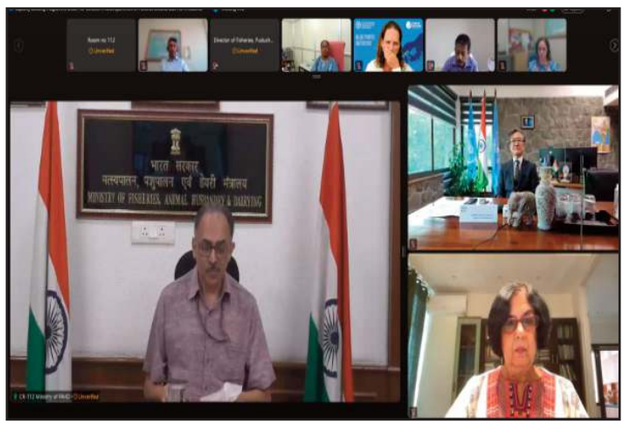

दोहराया। 5जी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी उन्नत तकनीकों के एकीकरण पर जोर देते हुए, उन्होंने मछली पकड़ने के बंदरगाहों पर दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिकीकरण और हितधारक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) जैसी प्रमुख योजनाओं के योगदान को रेखांकित किया और बंदरगाह संचालन में जलवायु लचीलापन, पता लगाने की क्षमता और ऊर्जा रुपांतरण पर ध्यान देने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का आ'ान किया। वनकबारा (दीव) और जखाऊ (गुजरात) बंदरगाहों पर कार्यनीतिक अपग्रेड के संचालन में एफएओ की सहायता का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएमएमएसवाई के तहत, गुजरात, दमन और दीव तथा पुडुचेरी में 369.80 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ तीन स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह विकसित किए जा रहे हैं।

वेबिनार में एफएओ के अधिकारियों, जिनमें श्री जोस एस्टोर्स, सुश्री योलांडा मोलारेस और सुश्री लूसिया लोपेज डी आरागॉन शामिल थे, ने ब्लू पोर्ट्स की अवधारणा और कार्यकुशलता बढ़ाने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सामाजिक-आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के लिए टिकाऊ, समावेशी और नवीन प्रथाओं को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर विशेषज्ञ प्रस्तुतियां दीं। इन सत्रों में बंदरगाहों को स्थिरता और मजबूत हितधारक सहयोग की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप, विगो बंदरगाह (स्पेन) पर एक केस स्टडी शामिल थी, जिसमें भारत में ब्लू पोर्ट्स दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रमुख चुनौतियों और संभावित कार्रवाइयों पर सफल कार्यान्वयन और भागीदारीपूर्ण चचाओं को प्रदर्शित किया गया। वेबिनार ने वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

इस कार्यक्रम में एफएओ मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, विगो बंदरगाह (स्पेन) के प्रतिनिधियों, तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, समुद्री बोर्डों, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों, मत्स्य सहकारी समितियों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भी भाग लिया।

दूरसंचार विभाग 'विशेष स्वच्छता अभियान 5.0' (2 अक्टूबर, 2025 - 31 अक्टूबर, 2025) के लिए तैयार

नवंबर 2024 - अगस्त 2025 के दौरान 60052 लोक शिकायतों, 257 सांसद संदर्भों, 96 राज्य सरकार संदर्भों और 13816 पीजी अपीलों का निपटारा किया गया

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) 2 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 को आरंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अभियान, जो अब विभाग की जारी पहलों का एक अभिन्न अंग है, का उद्देश्य प्रचालन को और अधिक सुव्यवस्थित करना, लंबित मुद्दों का समाधान करना और देश भर में अपने संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में एक स्वच्छ, अधिक कुशल कार्य वातावरण में योगदान करना है।

लंबित मामलों की पहचान, जिनमें सांसद संदर्भ, राज्य सरकार संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन और प्रधानमंत्री संदर्भ शामिल हैं, 15 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक की जा रही है। इसके बाद, समय पर समाधान और अधिक स्वच्छ, अधिक संगठित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अभियान आधिकारिक तौर पर पूरी गति से आरंभ हो जाएगा, जो पारदर्शिता और कुशल सेवा वितरण के लिए विभाग की प्रतिबद्धता में एक और बड़ी उपलब्धि होगी।

2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक आयोजित विभाग का विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 अत्यधिक सफल रहा। पूरे भारत में 600 से ज्यादा अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 2.63 करोड़ रुपये मूल्य के कबाड़ की बिक्री हुई और लगभग 60,000 वर्ग फुट जगह खाली हुई। इस उपलब्धि में अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी ने अहम भूमिका निभाई।

तब से, विभाग ने अपने प्रयास जारी रखे हैं और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। नवंबर 2024 और अगस्त 2025 के बीच, दूरसंचार विभाग ने कई महत्वपूर्ण मामलों का समाधान किया, जिनमें शामिल हैं:

- 60,052 जन शिकायतें
- 257 सांसद संदर्भ
- 96 राज्य सरकार संदर्भ
- 13,816 लोक शिकायत अपीलें

बीएसएनएल सर्किल कार्यालय, बेंगलुरु - डब्ल्यूएमएस कंपाउंड, बेंगलुरु : प्रचालनगत दक्षता बढ़ाने के अतिरिक्त, विभाग अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में, महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए एक क्रेच सुविधा का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है।

दूरसंचार विभाग विशेष स्वच्छता अभियान 5.0 को एक और बड़ी सफलता बनाने के लिए कृतसंकल्प है तथा प्रगति, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण के प्रति अपने निरंतर प्रयास को सुदृढ़ कर रहा है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

19 नवंबर तक जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस का ठहराव अहमदाबाद के स्थान पर साबरमती स्टेशन पर रहेगा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद स्टेशन पर चल रहे रेल भूमि विकास प्राधिकरण (फ्छऊअ) द्वारा पुनर्विकास कार्यों के कारण जोधपुर-हडपसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव अस्थाई तौर पर आगामी 60 दिनों तक अहमदाबाद के स्थान पर साबरमती स्टेशन पर यथावत रहेगा। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

- ट्रेन संख्या 20496/20495 जोधपुर - हडपसर - जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ठहराव 19-09-2025 से 19-11-2025 तक अहमदाबाद के स्थान पर साबरमती स्टेशन पर यथावत रहेगा। यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करे। ट्रेन के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा मुंबई सेंट्रल मंडल में विशेष स्वास्थ्य अभियान के साथ 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' का शुभारंभ

मुंबई,

स्वस्थ नारी सशक्त परिवार

पश्चिम रेलवे द्वारा 17 सितम्बर, 2025 को राष्ट्रव्यापी पहल 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' का शुभारंभ करके महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित यह अनूठा अभियान निवारक स्वास्थ्य सेवा, जागरूकता कार्यक्रमों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिससे मजबूत परिवारों और स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्वास्थ्य इकाई में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह ने डॉक्टरों और वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें मुंबई सेंट्रल मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती आरती परिहार; पश्चिम रेलवे की अपर मुख्य स्वास्थ्य निदेशक डॉ. निशा सिंह; अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (अउटर) डॉ. सोनाली घुमरे; अउटर डॉ. स्वाति सिंह, अउटर डॉ. मीना कुमारी; मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉ. रोजलिन बेबी और डॉ. भारती शामिल थीं।

अपने संबोधन में श्री पंकज सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा एक प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। श्रीमती आरती परिहार ने इस पहल की सराहना की और महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य जाँच शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित किया।

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्वास्थ्य इकाई

सब-डिविजनल हॉस्पिटल, वलसाड

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया गया, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेसर, हीमोग्लोबिन स्तर, ब्रेस्ट एवं स्त्री रोग संबंधी जाँच, ढअढ स्मीयर टेस्ट, ओरल कैंसर और टीबी की जाँच शामिल थी। किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर परामर्श सत्र आयोजित किए गए। डॉ. स्वाति सिंह ने महिलाओं के पोषण और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता पर एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी। जे.जे. अस्पताल के टीबी सुपरवाइजर ने क्षय रोग जाँच पर एक व्याख्यान भी दिया।

अभियान के क्रम में वलसाड के सब-डिविजन अस्पताल में महिला लाभार्थियों और बच्चों के लिए एक ऐसा ही स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में डॉ. सिम्मी गुप्ता (उटर) और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया और कार्यक्रम के उद्देश्यों, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का शीघ्र पता लगाने, एनीमिया, कैंसर जागरूकता, पोषण के महत्व आदि और स्वस्थ जीवन जीने के तरीकों पर चर्चा की। पोषण माह के शुभारंभ के उपलक्ष्य में, वलसाड अस्पताल में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम युक्त खाद्य उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।

श्री विनीत अभिषेक ने बताया कि मुंबई सेंट्रल और वलसाड में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविरों में 200 से ज्यादा महिलाओं और किशोरियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान रक्तचाप और रक्त शर्करा की निगरानी, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जाँच, स्त्री रोग संबंधी जाँच और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण सहित कई तरह की जाँचें की गईं।

इन कार्यक्रमों ने सफलतापूर्वक इस संदेश को पुष्ट किया कि स्वस्थ महिलाएं मजबूत परिवारों और स्वस्थ राष्ट्र की नींव हैं, और यह महिलाओं को अपने कल्याण की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त भी बनाता है।

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा 70वें रेल सेवा पुरस्कार का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया

मुंबई,

समर्पण की पहचान, उत्कृष्टता को प्रेरणा

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने अपने कर्मचारियों के अथक और समर्पित प्रयासों को मान्यता देने के लिए 70वें रेल सेवा पुरस्कार का आयोजन भव्यता और उत्साह के साथ किया।

इस प्रतिष्ठित समारोह के मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री पंकज सिंह थे, जिन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता भी की। श्री सिंह ने पश्चिम रेलवे में सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने में कर्मचारियों की ईमानदारी, अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना की।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुंबई सेंट्रल मंडल के विभिन्न विभागों के कुल 143 कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पित सेवा के लिए व्यक्तिगत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न टीमों को उनकी सहयोगात्मक उपलब्धियों और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए 29 विभागीय शील्ड प्रदान की गईं, जो टीम वर्क की प्रबल भावना को दशार्ती हैं।

अपने संबोधन में श्री पंकज सिंह ने उन कर्मचारियों के प्रयासों की प्रशंसा की, जो लगातार चुनौतियों का सामना करते हैं और इस बात पर जोर दिया कि उनका समर्पण पश्चिम रेलवे में दक्षता, सुरक्षा और यात्री संतुष्टि बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने परिचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने में सामूहिक ज़िम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और मुंबई सेंट्रल मंडल के कर्मचारियों द्वारा मानसून अवधि के दौरान किए गए चुनौतीपूर्ण कार्य की विशेष सराहना की।

इस कार्यक्रम में मुंबई सेंट्रल मंडल के सभी वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने पुरस्कार विजेताओं की सराहना की। यह रेल सेवा पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत और विभागीय उत्कृष्टता का सम्मान करता है, बल्कि एक सशक्त प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है, जो कर्मचारियों को सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और पश्चिम रेलवे के सुरक्षित, कुशल और यात्री-अनुकूल संचालन के मिशन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करता है।

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में अहमदाबाद मण्डल निभा रहा है अहम भूमिका

साबरमती से ध्रांगध्रा के बीच दूसरी स्वच्छता स्पेशल ट्रेन चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश

स्वच्छता अभियान के दूसरे दिन किया गया 10 ट्रक से अधिक कचरे का उचित निस्तारण

'स्वच्छता ही सेवा' (रल्हर) 2025 पूरे देश में 17 सितम्बर से प्रारंभ हुआ, जो 2 अक्टूबर, 2025 को गांधी जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। इस वर्ष के अभियान का थीम 'स्वच्छोत्सव' रखा गया है। इस अभियान में कार्यस्थलों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सफाई मित्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण मित्र एवं शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम और स्वच्छता के प्रति व्यापक जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अहमदाबाद मण्डल द्वारा 18.09.2025 को 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत साबरमती से ध्रांगध्रा के बीच चलाई दूसरी स्वच्छता विशेष ट्रेन चलाई गई, जिसमें इंजीनियरिंग, वाणिज्य, परिचालन, यांत्रिक, सिगनल एवं दूर संचार, विद्युत, कार्मिक, लेखा, चिकित्सा एवं आरपीएफ आदि विभागों के एक-एक अधिकारियों/सुपरवाइजर के साथ प्रत्येक विभाग के 15 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए।

साबरमती स्टेशन (जेल साइड) पर एक व्यापक श्रमदान और गहन सफाई अभियान चलाया गया। हर कोने को पूरी लगन और एकजुटता के साथ साफ किया गया, जहां रेलवे स्टाफ, स्वयंसेवक और अधिकारी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इसके बाद

स्वच्छता विशेष ट्रेन ने अपनी यात्रा आरंभ की जो साबरमती, झुंड, सडला, बजाना, जत पिपली, वसाडवा, ध्रांगध्रा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकी। हर ठहराव पर रेलवे कर्मियों ने सफाई अभियानों और जनजागरूकता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की, जिससे स्टेशन अधिक स्वच्छ हो सके। इस दौरान लगभग 10 ट्रक कचरा जमा कर उसका निस्तारण किया गया।

"स्वच्छता ही सेवा" (रल्हर) का मुख्य उद्देश्य देशभर में व्यापक जनभागीदारी को प्रेरित करना और स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, एकल-उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर जागरूकता पैदा करना है। इस क्रम में रेल मंत्रालय द्वारा 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।

रेलवे इकाइयों द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर एवं पीपीई किट व अन्य उपकरणों का वितरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता को जन आंदोलन का स्वरूप देने हेतु मैराथन, साइक्लोथॉन एवं वॉकथॉन जैसे आयोजन, वृक्षारोपण, कार्यालयों, भवनों, रेलवे ट्रैकों, स्टेशनों, ट्रेनों एवं रेलवे परिसरों में व्यापक साफ-सफाई की जाएगी तथा घर-घर जाकर नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा।

अहमदाबाद, पालनपुर, महेसाणा, गांधीधाम आदि रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार जैसे रेलवे स्टेशन, कॉलोनियाँ आदि में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन तथा पीपीई किट व अन्य उपकरणों का वितरण किया गया।

इस अभियान में कार्यस्थलों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सफाई मित्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण मित्र एवं शून्य अपशिष्ट कार्यक्रम और स्वच्छता के प्रति व्यापक जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अहमदाबाद मण्डल आम जनता से अपील करता है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेकर स्वच्छता को एक जन आंदोलन में बदलने और स्वच्छ भारत के निर्माण में योगदान दें। यह वार्षिक अभियान स्वैच्छिक और सामूहिक भागीदारी को सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।

उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 के तीसरे संस्करण में 85 से अधिक देशों के 500 से अधिक खरीदार व्यावसायिक अवसरों की खोज करेंगे

भारत 25-29 सितंबर, 2025 को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होने वाले तीसरे उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो (यूपीआईटीएस) 2025 में अपने सबसे बड़े रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, 85 से अधिक देशों के 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार स्थानीय निर्यातकों और निमार्ताओं से मिलेंगे और विचारों, उत्पादों और अवसरों का व्यापक आदान-प्रदान करेंगे।

पाँच दिनों के दौरान, ये खरीदार, जिनमें सभी जी20 देशों : अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रूस और चीन के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं, 2,400 प्रदर्शकों और 1,00,000 से ज्यादा विक्रेताओं के साथ बातचीत करेंगे।

इस आयोजन से भारी मात्रा में व्यवसाय सृजित होने का अनुमान है, जो इसे भारत की व्यापार यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बना देगा। इसका परिणाम केवल नए निर्यात ऑर्डर तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि संयुक्त उद्यम, तकनीकी गठजोड़ और यहाँ तक कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) भी होगा, जो दीर्घकालिक व्यावसायिक साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा।

फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन ने कहा कि "यूपीआईटीएस 2025 केवल एक व्यापार मेला नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश और दुनिया के बीच एक सेतु है। 85 से अधिक देशों के 500 से अधिक खरीदारों को अपने निर्यातकों से जोड़कर, हम ऐसे अवसर पैदा कर रहे हैं जो व्यापार से परे हैं - ऐसी साझेदारियाँ जो उद्योगों को बदल सकती हैं, निवेश ला सकती हैं और उत्तर प्रदेश के विनिर्माण इकोसिस्टम की असली ताकत का प्रदर्शन कर सकती हैं।"

नागर विमानन महानिदेशालय ने मॉनसून अंतराल के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दी

सुरक्षित और निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने के लिए उन्नत सुरक्षा उपायों के साथ हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर शुरू होंगी

नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीसीए, एएआई और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए कई बैठकें कीं

(जीएनएस)।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मॉनसून अंतराल के बाद 15/16 सितंबर 2025 से चारधाम यात्रा 2025 के लिए हेलीकॉप्टर परिचालन फिर से आरंभ करने की स्वीकृति दे दी है।

नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू के नेतृत्व में गहन समीक्षा के बाद चारधाम यात्रा और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु महत्वपूर्ण पहल की गई है। सुरक्षा में कोई चूक बिल्कुल बर्दाश्त न करने के स्पष्ट आदेश के साथ, डीजीसीए को सख्त कदम उठाने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री राममोहन नायडू ने डीजीसीए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राज्य सरकार और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून और दिल्ली में कई समीक्षा बैठकें कीं।

नागर विमानन मंत्री के निर्देशों के अनुसार, डीजीसीए ने 13 से 16 सितंबर 2025 तक अपनी टीम द्वारा सभी हेलीपैड, हेलीकॉप्टरों, संचालकों की तैयारियों और सहायता सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण/आकलन किया। इसके बाद उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को संचालन फिर से आरंभ करने की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सभी हेलीकॉप्टर संचालक कंपनियों और पायलटों को चुनौतियों तथा तीर्थयात्रा संचालन से संबंधित परिपत्र में अपनाए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई।

हेलीकॉप्टर द्वारा चारधाम की यात्रा के दो घटक हैं: पहला देहरादून (सहस्त्रधारा) से यमुनोत्री/गंगोत्री/केदारनाथ/बद्रीनाथ तक चार्टर सेवाएं और दूसरा गुप्तकाशी/फाटा/सीतापुर क्लस्टर से श्री केदारनाथ जी हेलीपैड तक शटल सेवाएं। कुल छह हेलीकॉप्टर संचालक गुप्तकाशी/फाटा/सीतापुर क्लस्टर से हेलिकॉप्टर शटल संचालन करेंगे और सात ऑपरेटर/संघ देहरादून (सहस्त्रधारा) से चार्टर उड़ान संचालित करेंगे।

उत्तराखंड के अति-ऊंचाई और दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित तीर्थस्थलों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने में हेलीकॉप्टर सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हुए, डीजीसीए ने सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाए हैं। डीजीसीए चारधाम यात्रा हेलीकॉप्टर संचालन पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखेगा। मई-जून 2025 में चारधाम सेक्टर में कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद, विभिन्न उच्चाधिकार प्राप्त समितियों ने सुरक्षित हेलीकॉप्टर संचालन में सुरक्षा उपायों की सिफारिश की थी, जिनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण - एएआई द्वारा हवाई यातायात नियंत्रकों, भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम विज्ञान अधिकारियों और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूसीएडीए) द्वारा नियंत्रण कक्षों में योग्य कर्मियों की तैनाती शामिल है।

डीजीसीए द्वारा कार्यान्वित प्रमुख सुरक्षा पहल :

पायलट क्षमता और प्रशिक्षण गहन बनाया गया

चारधाम सेक्टर पर उड़ान भरने वाले सभी पायलटों के लिए अनिवार्य मार्ग जांच और आवर्ती प्रशिक्षण।

अति ऊंचाई पर संचालन, खराब मौसम से निपटने और चालक दल के संसाधन प्रबंधन पर विशेष जोर।

इस क्षेत्र में उड़ान अनुभव वाले योग्य पायलटों की ही तैनाती।

उन्नत उड़ान योग्यता निरीक्षण

यात्रा में इस्तेमाल होने वाले सभी हेलीकॉप्टरों का सघन उड़ान योग्यता निरीक्षण।

परिचालन सत्र के दौरान जांच की बारंबरता बढ़ाने के साथ हेलिकॉप्टर निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा अनुशंसित रखरखाव का सख्ती से पालन।

परिचालन सुरक्षा उपाय

चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षित उड़ान और लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए वजन और संतुलन का सख्त पालन।

स्थितिजन्य जानकारी के लिए आधुनिक नेविगेशन और संचार सहायता का अनिवार्य उपयोग।

समर्पित सूचना प्रणाली द्वारा पायलटों के लिए वास्तविक समय अपडेट के साथ उन्नत मौसम निगरानी।

हवाई यातायात सेवाओं की सलाहकार क्षमता

यात्री सुरक्षा एवं जागरूकता

हेलिकॉप्टर में सवार होने से पहले सभी यात्रियों को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी, जिसमें सीट बेल्ट का उपयोग, सुरक्षित रूप से चढ़ने/उतरने की जानकारी तथा आपातकालीन स्थिति में उठाए जाने वाले उपायों की जानकारी शामिल होंगी।

यात्रियों की आवाजाही में सहायता और उन्हें नियंत्रित करने के लिए हेलीपैड पर अतिरिक्त ग्राउंड सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती।

सुदृढ़ नियामक निगरानी

डीजीसीए की उड़ान परिचालन और उड़ान योग्यता टीमें जमीनी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हेलीपैडों पर तैनात की जाएंगी।

एसईसीएल ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 75 कोयला श्रमिकों को सम्मानित किया

स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के अंतर्गत स्वच्छता शपथ दिलाई गई

(जीएनएस)।

कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन और भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित एक भव्य समारोह में 75

कोयला खनन कर्मियों को एसईसीएल विश्वकर्मा पुरस्कारों से सम्मानित किया। एसईसीएल विश्वकर्मा पुरस्कारों के पहले संस्करण में एसईसीएल की खदानों में खनन कार्यों, रखरखाव, पर्यवेक्षण और संबद्ध भूमिकाओं में कार्यरत कर्मियों के साहस, समर्पण और अनुकरणीय सेवा को सम्मानित किया गया।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रुप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसईसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहान ने की। इस अवसर पर एसईसीएल के कार्यकारी निदेशकगण, श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

श्री तोखन साहू ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर विश्वकर्मा पुरस्कार स्थापित करने की एसईसीएल की पहल की सराहना की।

गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत पौधे रोपे। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथि द्वारा स्वच्छता शपथ दिलाने के साथ हुई, जिसके साथ ही एसईसीएल मुख्यालय और परिचालन क्षेत्रों में "स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025" का शुभारंभ भी हुआ।

समारोह के एक भाग के रूप में, एसईसीएल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अपने दस परिचालन जिलों में "एसईसीएल-17: विश्वकर्मा सेवा संकल्प" नामक एक विशेष एक दिवसीय अभियान भी संचालित किया। इस अभियान में नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए सत्रह कल्याणकारी गतिविधियाँ शामिल थीं, जिनमें स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, सुरक्षा और सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता कार्यशालाएँ, "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत वृक्षारोपण अभियान और नशामुक्ति जागरूकता पहल सम्मिलित थीं। ये गतिविधियाँ कर्मचारियों के कल्याण, स्थायी प्रथाओं और सामुदायिक विकास के प्रति एसईसीएल की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ती हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रेन नं. 19206 महुवा-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस एवं ट्रेन नं. 59229 बोटाद-भावनगर टर्मिनस पैसेंजर के समय में परिवर्तन

यात्रियों की सुविधा, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार तथा सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा 22 सितम्बर, 2025 से ट्रेन नं. 19206 महुवा-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस एवं ट्रेन नं. 59229 बोटाद-भावनगर टर्मिनस पैसेंजर के समय में संशोधन किया गया है।

इन दोनों ट्रेनों के संशोधित समय नीचे अनुसार रहेंगे:

1. ट्रेन नं. 59229 - बोटाद-भावनगर टर्मिनस पैसेंजर

- बोटाद जं. से प्रस्थान अब प्रातः 06.50 बजे होगा (पूर्व समय 07.10 बजे था)।
- भावनगर टर्मिनस पर आगमन अब प्रातः 09.10 बजे होगा।
- मार्ग के प्रमुख स्टेशनों पर प्रस्थान समय 10 से 15 मिनट तक अग्रिम किया गया है।

2. ट्रेन नं. 19206 - महुवा-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस

- महुवा जं. से प्रस्थान दोपहर 03.10 बजे होगा (पूर्व समय 03.00 बजे था)।
- भावनगर टर्मिनस पर आगमन रात्रि 07.50 बजे अपरिवर्तित रहेगा।
- मध्यवर्ती स्टेशनों पर आगमन/प्रस्थान समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया है।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पूर्व अपने गंतव्य स्टेशनों के संशोधित आगमन एवं प्रस्थान समय की जानकारी वेबसाइट www. enquiry. indianrail. gov.in से अवश्य प्राप्त कर लें।

यह परिवर्तन 22 सितम्बर, 2025 से प्रभावी रहेगा।

भावनगर टर्मिनस से चलने वाली भावनगर - शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि एक्सप्रेस 12 अक्टूबर तक रद्द

यात्रियों की जानकारी हेतु सूचित किया जाता है कि परिचालन कारणों से पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल से चलने वाली भावनगर टर्मिनस - शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि एक्सप्रेस अस्थायी रूप से निरस्त रहेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार, विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 19107 भावनगर टर्मिनस - शहीद कप्तान तुषार महाजन जन्मभूमि एक्सप्रेस

दिनांक 21.09.2025, 28.09.2025, 05.10.2025 एवं 12.10.2025 को पूर्णतः निरस्त रहेगी।

2. ट्रेन संख्या 19108 शहीद कप्तान तुषार महाजन - भावनगर टर्मिनस जन्मभूमि एक्सप्रेस

दिनांक 22.09.2025, 29.09.2025, 06.10.2025 एवं 13.10.2025 को पूर्णतः निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा की योजना उपरोक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बनाएं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 सितंबर को लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की समीक्षा बैठक और निरीक्षण करेंगे

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 18 सितंबर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वे अहमदाबाद जिले के लोथल में निमार्णाधीन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (एनएमएचसी) प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही अब तक हुए कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ समग्र प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा करेंगे और लोथल में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी भी हासिल करेंगे।

उल्लेखनीय है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यापारिक केंद्र होने के साथ-साथ भारत की समुद्री (मैरीटाइम) शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी था। ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के गवाह लोथल में भारत की भव्य समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने वाला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आकार ले रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने द्वारा दिए गए 'पंच प्राण' में से एक प्राचीन

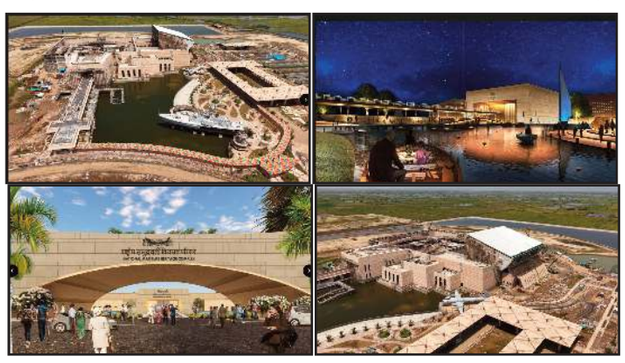

विरासतों पर गर्व कर उनका संरक्षण करना है, जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्कस के निर्माण के जरिए साकार होने जा रहा है।

'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स

नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में इतिहास, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन का एक सुंदर समन्वय होगा। लगभग 5 हजार वर्ष पहले लोथल न केवल एक बंदरगाह था, बल्कि यहां समुद्री जहाजों की मरम्मत का काम भी होता था। उस इतिहास को यहां फिर से जीवंत किया जाएगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भव्य और प्राचीन समुद्री विरासत की अनुभूति कराई जाएगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता के कारण इस अति प्राचीन स्थल का दोबारा विकास संभव हुआ है। गुजरात की प्राचीन धरोहर का एक महत्वपूर्ण स्थान लोथल, एक बड़े बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। इस प्रकार, गुजरात की समृद्ध प्राचीन समुद्री विरासत को आधुनिक युग के आयामों के साथ जोड़कर तैयार किया जा रहा यह म्यूजियम प्रधानमंत्री के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा।

हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के कारण हजारों लोगों के लिए उपलब्ध होंगे रोजगार के अवसर

यह हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के अलावा अध्ययन का एक केंद्र भी बनेगा। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एक नए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे दुनिया के अन्य प्रतिष्ठित म्यूजियमों के समकक्ष बनाए रखा जाएगा। यह प्रोजेक्ट पूरे भाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

सहकार से समृद्धि की सफलता गाथा: बनासकांठा की मानीबेन ने 2024-25 में ₹1.94 करोड़ का दूध बेचा, इस वर्ष ₹3 करोड़ का लक्ष्य

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 18 सितंबर :देश के सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना और उसके माध्यम से देश के प्रत्येक गाँव के किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात राज्य सहकारी क्षेत्र में पूरे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सहकारिता क्षेत्र में हुए व्यापक प्रयासों के परिणामस्वरूप आज राज्य के पशुपालक समृद्ध हो रहे हैं और विशेष रूप से महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर समाज को प्रेरणा दे रही हैं। ऐसी ही एक सफलता गाथा बनासकांठा की मानीबेन की है, जिन्होंने वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ 94 लाख रुपये का दूध संग्रहित कर बनासकांठा जिले में दूसरा स्थान प्राप्त

किया है। इस वर्ष वे 3 करोड़ रुपये का दूध बेचने का लक्ष्य प्राप्त करने की तैयारी कर रही हैं।

कांकरेज तालुका के कसरा गाँव की 65 वर्षीय मानीबेन जेसुंगभाई चौधरी स्थानीय दि पटेलवास (कसरा) दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडली में प्रतिदिन 1100 लीटर दूध जमा कराती हैं। वर्ष 2024-25 में उन्होंने कुल 3 लाख 47 हजार से अधिक लीटर दूध जमा कराया, जिसका मूल्य ₹1 करोड़ 94 लाख से अधिक हुआ है। अपनी इस उपलब्धि के कारण उन्हें इस वर्ष पूरे बनासकांठा जिले में 'श्रेष्ठ बनास लक्ष्मी' श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में बनासकांठा के बादरपुरा में आयोजित आमसभा में उन्हें इस सफलता के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया।

इस वर्ष 100 नई भैंसें खरीदने की तैयारी में हैं मानीबेन चौधरी

मानीबेन अपनी इस सफलता को नई ऊँचाइयों तक ले जाना चाहती हैं। उनके परिवार में तीन बेटों में सबसे छोटे विपुलभाई ने बताया, 'हमें बनास डेयरी से समय-समय पर उचित मार्गदर्शन मिल रहा है और हम इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2011 में हमारे पास केवल 10 से 12 गाय और भैंस थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 230 से अधिक हो गई है। वर्तमान में हमारे पास 140 भैंसें, 90 गायें और लगभग 70 छोटे बछड़े हैं।

भारत के सात प्राकृतिक विरासत स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल

(जीएनएस)।

नई दिल्ली: भारत अपनी समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर संरक्षित और प्रदर्शित करने में लगातार महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय गौरव के इस क्षण में, देश भर के सात उल्लेखनीय प्राकृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में सफलतापूर्वक शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस संभावित सूची में भारत के विरासत स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है।

अब भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल 69 स्थल हैं, जिनमें 49 सांस्कृतिक, 17 प्राकृतिक और 3 मिश्रित विरासत स्थल शामिल हैं। यह उपलब्धि भारत की असाधारण प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दशार्ती है।

यूनेस्को के प्रोटोकॉल के अनुसार, प्रतिष्ठित विश्व विरासत सूची में नामांकित होने के लिए किसी भी स्थल का संभावित सूची में शामिल होना आवश्यक है।

संभावित सूची में शामिल हुए नए स्थलों का विवरण:

महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर स्थित डेक्कन ट्रैप: दुनिया के कुछ सर्वोत्तम संरक्षित और अध्ययन किए गए लावा प्रवाहों का घर, ये स्थल विशाल डेक्कन ट्रैप का हिस्सा हैं और उस कोयना वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित हैं जो पहले से ही यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है।

कर्नाटक में सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत: अपनी दुर्लभ स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं के लिए जाना जाने वाला, यह द्वीप समूह उत्तर क्रेटेशियस काल का है, जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पूर्व का भूवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करता है।

मेघालय में मेघालय युग की गुफाएं: मेघालय की आश्चर्यजनक गुफा प्रणालियां, विशेष रूप से माव्लुह गुफा, होलोसीन युग में मेघालय युग के लिए वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती हैं, जो महत्वपूर्ण जलवायु और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को दशार्ती हैं।

नागालैंड की नागा हिल ओफियोलाइट: ओफियोलाइट चट्टानों का एक दुर्लभ प्रदर्शन, ये पहाड़ियां महाद्वीपीय प्लेटों पर उभरी हुई महासागरीय परत का प्रतिनिधित्व करती हैं—जो टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और मध्य-महासागरीय रिज की गतिशीलता की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

आंध्र प्रदेश में एर्रा मट्टी डिब्बालु (लाल रेत की पहाड़ियां): विशाखापत्तनम के पास ये आकर्षक लाल रेत की संरचनाएं अद्वितीय पुरा-जलवायु और तटीय भू-आकृति विज्ञान संबंधी विशेषताओं को दशार्ती हैं जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और गतिशील विकास को प्रकट करती हैं।

आंध्र प्रदेश में तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत: एपार्चियन नादुरुस्ती (अनकन्फॉर्मिटी) और प्रतिष्ठित सिलाथोरनम (प्राकृतिक मेहराब) की विशेषता वाला यह स्थल अत्यधिक भूवैज्ञानिक महत्व रखता है। यह पृथ्वी के 1.5 अरब वर्षों से अधिक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।

केरल में वर्कला चट्टानें: केरल के समुद्र तट के किनारे स्थित सुंदर चट्टानें, प्राकृतिक झरनों और आकर्षक अपरदनकारी भू-आकृतियों के साथ, मायो-प्लियोसीन युग के वर्कल्ली संरचना को उजागर करती हैं, जो वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों ही दृष्टि से मूल्यवान हैं।

वैश्विक विरासत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

इन स्थलों को संभावित सूची में शामिल करना भविष्य में विश्व विरासत सूची में इनके नामांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह भारत के प्राकृतिक अजूबों को वैश्विक संरक्षण प्रयासों के साथ एकीकृत करने के रणनीतिक लक्ष्य को दशार्ता है।

भारत की ओर से विश्व विरासत सम्मेलन के लिए नोडल एजेंसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने नामांकनों को संकलित करने और प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूनेस्को, पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस प्रयास में एएसआई के समर्पित कार्य के लिए उसकी हार्दिक सराहना की।

भारत ने जुलाई 2024 में नई दिल्ली में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र की भी गर्व से मेजबानी की। इस सत्र में 140 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

सेवा पर्व - 2025: विकसित भारत की रचनात्मक अभिव्यक्ति में राष्ट्र एकजुटता

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पर्व - 2025 को सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के एक राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, सेवा पर्व का उद्देश्य समुदायों, संस्थानों और व्यक्तियों को सेवा, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव के एक सामूहिक आंदोलन में एक साथ लाना है ।

संस्कृति मंत्रालय, समारोह के एक भाग के रूप में, देश के 75 प्रमुख स्थानों पर अपने संगठनों और संस्थानों के माध्यम से "विकसित भारत के रंग, कला के संग" टैगलाइन के अंतर्गत "विकसित भारत" विषय पर एक-दिवसीय चित्रकला और कला कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। ये कार्यशालाएं पेशेवर कलाकारों, छात्रों, स्कूली बच्चों और नागरिकों को विकसित भारत के दृष्टिकोण को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने में संलग्न करने के लिए डिजाइन की गई हैं।

17 सितंबर 2025 को समारोह

संस्कृति मंत्रालय के संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों ने उद्घाटन के दिन पूरे देश में चित्रकला कार्यशालाओं और कला शिविरों का आयोजन किया जो जनभागीदारी की सच्ची भावना को दशार्ता है।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश (लखनऊ

क्षेत्रीय केंद्र द्वारा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, एनसीजेडसीसी) के सहयोग से आयोजित एक विशाल कला कार्यशाला में 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना, माननीय विधायक श्री नीरज बोहरा, वरिष्ठ कुलपति तथा पद्मश्री पुरस्कार विजेता विद्या बिंदु सिंह और मालिनी अवस्थी ने भाग लिया।

वडोदरा, गुजरात (आईजीएनसीए क्षेत्रीय केंद्र) - 1) लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, हरनी और 2) पारुल विश्वविद्यालय में कार्यशालाओं में प्रख्यात कलाकारों के मार्गदर्शन में 2,000 से अधिक छात्रों और कलाकारों ने भाग लिया ।

जम्मू, जम्मू और कश्मीर (आईजीएनसीए क्षेत्रीय केंद्र) - कन्वेंशन सेंटर, कैनाल रोड में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 1,300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में प्रोफेसर उमेश राय (कुलपति, जम्मू विश्वविद्यालय), श्री रमेश कुमार (मंडल आयुक्त) और पद्मश्री मूर्तिकार राजेंद्र टिक्कू जैसे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

तंजावुर, तमिलनाडु (दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र) - एसजेडसीसी मुख्यालय में, पेशेवर कलाकारों, कॉलेज के छात्रों और स्कूली बच्चों सहित लगभग 100 प्रतिभागियों ने वरिष्ठ कलाकारों और प्रोफेसरों की एक प्रतिष्ठित जूरी द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया।

हैदराबाद, तेलंगाना (सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र) - 500 से अधिक प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक शिक्षकों और कलाकारों के साथ इंटरैक्टिव पेंटिंग सत्र में भाग लिया।

दमोह, मध्य प्रदेश (सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र) - श्रीमती प्रीति सिंह (जनपद पंचायत अध्यक्ष) एवं श्री एस.के. नेमा (जिला शिक्षा अधिकारी) द्वारा उद्घाटन सेवा पर्व-2025 कला कार्यशाला में लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल (ईजेडसीसी में सृजनी शिल्पग्राम) - कला कार्यशालाओं में 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें पद्मश्री सुजीत चट्टोपाध्याय और भारत सेवा आश्रम के प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही। आणंद, गुजरात (डब्ल्यूजेडसीसी) - सेवा पर्व-2025 कला कार्यशाला का आयोजन ज़िला प्रमुखों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया जिसमें 300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी 'शंकर' की अचानक मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए

16 सितंबर, 2025 तक कोई बीमारी या असामान्य व्यवहार की सूचना नहीं थी

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (एनजेडपी), नई दिल्ली ने 17 सितंबर, 2025 की रात 8:00 बजे 29 वर्षीय नर अफ्रीकी हाथी 'शंकर' के अचानक निधन की सूचना दी है।

मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आगे की जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) बरेली, स्वास्थ्य सलाहकार समिति और मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम और आवश्यक नमूने लेने के बाद, शव का उचित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाएगा।

नवंबर, 1998 में ज़िम्बाब्वे से आने के बाद, 'शंकर' 27 वर्षों से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा था। आगंतुक उसकी प्रशंसा करते थे और चिड़ियाघर के कर्मचारी उसके सौम्य स्वभाव और राजसी उपस्थिति के लिए उसे बहुत महत्व देते थे।

17 सितंबर की सुबह यह देखा गया कि 'शंकर' कम पत्ते और घास खा रहा था और उसे हल्का दस्त भी हो रहा था, लेकिन वह फल और सब्ज़ियां सामान्य रूप से ले रहा था। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की पशु चिकित्सा टीम ने उसका उपचार किया और पशुपालन कर्मचारियों ने कड़ी निगरानी रखी।

उसी दिन शाम लगभग 7:25 बजे शंकर अचानक शेड में गिर पड़ा। आपातकालीन उपचार के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। 16 सितंबर 2025 तक किसी भी बीमारी या असामान्य व्यवहार की सूचना नहीं थी।

'शंकर' शक्ति, बुद्धि और प्रेम के प्रतीक था और चिड़ियाघर के कई सदस्य उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के निदेशक डॉ. संजीत कुमार ने कहा कि उनके निधन से उत्पन्न शून्य को चिड़ियाघर की टीम, आगंतुकों और संपूर्ण संरक्षण समुदाय गहराई से महसूस करेगा। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और पूरे देश में चल रहे वन्यजीव कल्याण और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के

डीएफएस सचिव ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की ओर से आयोजित 'एमएसएमई का सशक्तिकरण: अवसर, चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर बैठक की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

डीएफएस सचिव ने आज नई दिल्ली में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की ओर से आयोजित 'एमएसएमई का सशक्तिकरण: अवसर, चुनौतियां और आगे की राह' विषय पर बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक, आईबीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ देश भर के एमएसएमई उद्योग संघों ने भाग लिया।

मुख्य भाषण में, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने रेखांकित किया कि एमएसएमई भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो भारत की जीडीपी में 30% और निर्यात में 45% से अधिक का योगदान देते हैं और उद्यमशीलता, रोजगार और समावेशी विकास को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर पर आर्थिक बदलाव को गति देते हैं। उन्होंने इस विषय पर प्रकाश डाला कि भारत का विविध एमएसएमई क्षेत्र पारंपरिक उद्योगों से लेकर आधुनिक

तकनीक तक फैली अपनी मजबूत उद्यमशीलता की भावना को प्रदर्शित करता है और समावेशी विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को प्रोत्साहन देकर विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक बेहतर पहुंच के साथ उन्हें सशक्त बनाना एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण की कुंजी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उद्योग, सरकार और वित्तीय संस्थान एक साथ काम कर, एमएसएमई क्षेत्र के लिए नए अवसर खोल सकते हैं।

इस क्षेत्र के लिए भारत सरकार की पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में डिजिटल ऋणों की ओर पूर्ण रूप से रुख, मजबूत कैश फ्लो आधारित अंडरराइटिंग मॉडल, विलंबित भुगतान, एमएसएमई जागरूकता में सुधार, डेटा गुणवत्ता में सुधार, वित्त तक पहुंच में सुधार और अन्य क्षेत्रों में सुझावों पर चर्चा की गई।

चर्चाओं में इस क्षेत्र के लिए अधिक जिम्मेदार नीतियां और प्रभावशाली समर्थन प्रणालियां बनाने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं।

एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 होगी

विशिष्ट परिस्थितियों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा उपलब्ध कराई गई

(जीएनएस)।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 24.01.2025 की अधिसूचना संख्या एफ. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर के माध्यम से पात्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अधिसूचित की थी। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि एनपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। सभी पात्र कर्मचारियों से आग्रह है कि वे अंतिम समय में आने वाली किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस नहीं चुन सकते।

इसके अलावा, डीएफएस ने दिनांक 25.08.2025 को एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/2024-पीआर जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की गई है, जिन्होंने पहले ही यूपीएस का विकल्प चुना है, जिससे उन्हें निर्दिष्ट शर्तों के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस लौटने की अनुमति मिलती है:

यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते।

स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।

दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, वहां स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफॉल्ट रूप से यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।

जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितम्बर 2025 के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।

इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प बरकरार रख सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा के लिए एसपीआरईई 2025 पर जोर

ईएसआईसी हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय ने ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया

(जीएनएस)।

कर्मचारी कल्याण कानूनों और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय ने फरीदाबाद प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य स्कूल अधिकारियों और प्रतिष्ठान मालिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के वैधानिक प्रावधानों और ईएसआई योजना के पंजीकरण के लाभों के बारे में शिक्षित करना था।

कार्यक्रम में ईएसआई अधिनियम के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक स्कूल, कारखाने, क्लिनिक, अस्पताल, दुकान या प्रतिष्ठान को इस योजना के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने पर प्रकाश डाला गया है। 10 कर्मचारियों की सीमा पूरी होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर पंजीकरण पूरा किया जाना चाहिए। इस बात पर बल दिया गया कि ईएसआईसी पंजीकरण न केवल श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, बल्कि ईएसआई पंजीकरण न होने के मामलों में, नियोक्ताओं को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारियों से भी बचाता है।

प्रतिभागियों को बताया गया कि कई प्रतिष्ठान, वर्षों से पात्र होने के बावजूद, ईएसआईसी के साथ

पंजीकरण कराने में विफल रहे हैं, इससे उनके कर्मचारी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित हो रहे हैं। अनुपालन न करने पर पूर्वव्यापी अंशदान देनदारियां, ब्याज, दंड और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इन चिंताओं के समाधान और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईएसआईसी द्वारा शुरू की गई नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीआरईई) 2025 के बारे में जानकारी दी गई। यह योजना पात्र प्रतिष्ठानों को पूर्वव्यापी जांच या मांग के डर के बिना ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराने का अवसर प्रदान करती है। एसपीआरईई 2025 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

नए पंजीकृत प्रतिष्ठानों के पिछले अभिलेखों का निरीक्षण नहीं;

पिछले अंशदान, ब्याज या दंड की मांग नहीं;

पिछले गैर-अनुपालन के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं;

प्रतिष्ठान स्वामी का पंजीकरण पंजीकरण की तिथि से ही मान्य होगा।

एसपीआरईई 2025 के अंतर्गत, नियोक्ता और कर्मचारी ईएसआईसी के सभी लाभों का लाभ उठा सकते हैं। इनमें चिकित्सा देखभाल, बीमारी और मातृत्व लाभ, स्थायी विकलांगता और आश्रित पेंशन, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता, अंतिम संस्कार व्यय, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास शामिल हैं।

यह विशेष पंजीकरण योजना 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। इससे प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति को नियमित करने और अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए सीमित समय मिलेगा।

सहायता या स्पष्टीकरण चाहने वाले प्रतिष्ठान मालिक तत्काल सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन 0129-2222980/981 पर संपर्क कर सकते हैं।

इस संगोष्ठी में लगभग 40 नियोक्ताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व ईएसआईसी हरियाणा के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुगन लाल मीणा ने किया और ईएसआई योजना के तहत वैधानिक दायित्वों और लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। श्री टी.एस. दलाल (मुख्य संरक्षक), श्री नरेंद्र परमार (अध्यक्ष), श्री राजदीप सिंह (महासचिव), श्री भारत भूषण (कोषाध्यक्ष), श्री नारायण डागर, श्री साकेत भाटिया, श्री राकेश बंसल, श्री अनुभव माहेश्वरी, श्री तुलसी, श्री विनय गोयल, श्री विनोद, श्री मोहन और श्री भगवान सिंह आदि अन्य प्रमुख लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।